राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

रोकठोक लेखनी ®

RNI NO. : MAHHIN/2019/77511

खबरें बे-रोकटोक

वर्ष 07 ▪ अंक 42 ▪ मुंबई : बुधवार 26 अगस्त 2026 से 01 सितंबर 2026 ▪ संपादक : फैसल शेख ▪ पृष्ठ : 8 ▪ कीमत : 03 रुपये

मुंबई ऑटो हड़ताल: ड्राइवरों ने कहा...

60 साल में कौन सीखेगा मराठी, फडणवीस बोले- टूटी-फूटी काफी है

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई आई है। सोमवार 24 अगस्त को मुंबई के कई इलाकों में ऑटो ड्राइरों ने विरोध में हड़ताल की थी।

गैर-मराठी भाषी चालकों के बीच यह डर फैल गया कि मराठी नहीं बोल पाने पर उन पर भारी जुमार्ना लगाया जाएगा और उनका लाइसेंस या बैज रद्द किया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चालकों को मराठी का विशेषज्ञ या धाराप्रवाह वक्ता बनने की जरूरत नहीं है।

उन्हें सिर्फ यात्रियों से कामकाज से जुड़ा बुनियादी संवाद करने लायक मराठी जाननी होगी।

तीन दिन की हड़ताल का ऐलान

मुंबई में कुछ ऑटो-रिक्शा चालकों ने मराठी भाषा संबंधी निर्देश के विरोध में तीन दिन की हड़ताल शुरू की। चालकों का कहना है कि वे मराठी सीखने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उम्रदराज और कम पढ़े-लिखे लोगों से अचानक भाषा सीखने और परीक्षा पास करने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है।

एक 60 वर्षीय चालक ने कहा कि अगर इतने साल की उम्र में अचानक मराठी बोलने को कहा जाए तो यह आसान नहीं है। एक अन्य चालक, जिसने बताया कि उसने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, ने कहा कि वह टूटी-फूटी मराठी बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे भी पर्याप्त नहीं माना जा रहा। चालकों ने कथित तौर पर 15,000-20,000 रुपये तक के जुमार्ने की आशंका जताई और कहा कि वे अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हैं। हालांकि, एक ऑटो-टैक्सी यूनियन नेता ने कहा कि किसी प्रमुख यूनियन ने आधिकारिक तौर पर हड़ताल या आंदोलन का आह्वान नहीं किया था।

फडणवीस ने कहा- मराठी का प्रोफेसर बनना जरूरी नहीं

विरोध के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा का विशेषज्ञ बनाना नहीं है। फडणवीस के मुताबिक, चालकों को सिर्फ कामकाज से संबंधित बुनियादी मराठी आनी चाहिए, ताकि वे स्थानीय यात्रियों से आवश्यक बातचीत कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और जरूरत पड़ने पर चालकों को मराठी सीखने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक किसी चालक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, नियम का उद्देश्य मराठी भाषा, संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों और चालकों के बीच बुनियादी संवाद सुनिश्चित करना है।

1,268 और फिर 1,499 चालकों को नोटिस

आरटीओ ने 20 अगस्त को मराठी का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण 1,268 कमर्शियल पैसेंजर वाहन चालकों, मुख्य रूप से ऑटो और टैक्सी चालकों, को नोटिस जारी किए थे। इसके अगले दिन महाराष्ट्र भर में 1,499 गैर-मराठी भाषी चालकों को नोटिस दिए गए। परिवहन मंत्री सरनाईक ने यह भी बताया कि अब तक 1,65,600 गैर-मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों ने मराठी की कक्षाओं में हिस्सा लिया है। सरकार का तर्क है कि भाषा का उद्देश्य चालकों और यात्रियों के बीच बुनियादी संवाद सुनिश्चित करना है।

उनके मुताबिक, पश्चिमी मुंबई के उन इलाकों में कुछ समूहों ने प्रदर्शन किया जहां गैर-मराठी भाषी चालकों की संख्या ज्यादा है।

मुंबई की पार्षद विशाखा राउत का कुनबी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द

बीएमसी में उद्धव ठाकरे को झटका लगना तय...

मुंबई: मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मेयर और पार्षद विशाखा राउत को चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि पालघर जाति जांच कमेटी ने बीएमसी चुनाव लड़ते समय उनके जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे का एक पार्षद कम हो जाएगा। विशाखा राउत ने दादर के वार्ड 191 से शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व था। उन्होंने रिजर्व सीट के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक ओबीसी सर्टिफिकेट जमा किया था।

एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता सदा सरवणकर की बेटी प्रिया गुरव वार्ड संख्या 191 में विशाखा के सामने लड़ी थीं। वार्ड 191 से यूबीबी पार्षद विशाखा राउत के चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ मंगलवार को बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और राउत को अयोग्य ठहराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अमान्य कुनबी जाति सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ओबीसी-रिजर्व वार्ड से चुनाव लड़ा था। 24 अगस्त को बीएमसी कमिश्नर को दिए एक रिप्रेजेंटेशन में गुरव ने पालघर डिस्ट्रिक्ट जाति वेरिफिकेशन कमेटी के 20 अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसकी एक कॉपी उन्हें ईमेल से मिली थी।

उद्धव ठाकरे को लगेगा झटका

इसी साल की शुरूआत में हुए बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीती थीं। विशाखा राउत वर्ष 1997 से 1998 तक मुंबई (बृहन्मुंबई नगर निगम) की मेयर (महापौर) रही थीं। वह स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद मुंबई की पहली महिला मेयर बनी थीं। वह 1999 से 2004 तक दादर विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा की विधायक भी रह चुकी हैं। विशाखा राउत की सदस्यता रद्द होने से उद्धव ठाकरे को झटका लगेगा।

मुंबई: खिलाड़ियों को पता है कि वे 'नॉन-वेज चाय' पी रहे हैं?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफडीएको एमसीए किचन की दोबारा जांच का दिया निर्देश...

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) के किचन में अस्वच्छता और साफ-सफाई के नियमों के उल्लंघन पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या खिलाड़ियों को पता है कि वे 'नॉन-वेज चाय' पी रहे हैं? यह टिप्पणी कोर्ट ने एमसीए की रसोई में मक्खियां और कॉकरोच मिलने के खुलासे पर की है। कोर्ट ने एफडीए को 27 अगस्त को नए सिरे से एमसीए के 5 किचन का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

जांच में मिली थी गंदगी

एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुघे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच यह निर्देश एमसीए की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याचिका में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एमसीए के परिसर में चलने वाले पांच रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड करने के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के फैसले को चुनौती दी गई है। हाल ही में एफडीएकी जांच में इन रेस्टोरेंट की रसोई में कॉकरोच और मक्खियों की भरमार मिली थी। फर्श गंदा पाया गया था।

एफडीए कर सकत है लाइसेंस निलंबित

एफसीए की ओर से सीनियर ऐडवोकेट विक्रम ननकानी ने कहा कि लाइसेंस निलंबित करने से पहले एफडीएको सुधार नोटिस जारी करना चाहिए था, ताकि खामियों को दूर करने का मौका मिल सके। किचन बंद होने के कारण मैदान पर आने वाले क्रिकेटरों को चाय तक उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है। इस पर बेंच ने कहा कि यदि निरीक्षण में साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो एफडीए तत्काल लाइसेंस निलंबित कर सकता है।

मीरा-भाईंदर में कचरा घोटाला? ठेकेदार पर मेहरबान मनपा, बिना GPS और VTMS के बांटे जा रहे करोड़ों रुपए

मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के दैनिक सफाई और कचरा परिवहन के ठेके को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सफाई ठेकेदार ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट सेल प्राइवेट लिमिटेड को किए जा रहे भुगतानों के बीच अनुबंध में अनिवार्य बताई गई वीटीएमएस, जीपीएस, एमआईएस और बायोमेट्रिक, फेस रीडिंग जैसी सत्यापन प्रणालियों के प्रभावी रूप से चालू नहीं होने का मामला सामने आया है। मनपा के सदन नेता एड. रवि व्यास ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच तथा विशेष वित्तीय एवं तकनीकी ऑडिट की मांग की है।

सिस्टम बंद था तो भुगतान किस आधार पर ?

एड. रवि व्यास ने मनपा प्रशासन के ही पत्राचार का हवाला देते हुए कहा है कि ठेकेदार के काम के तकनीकी सत्यापन के लिए आवश्यक कुछ प्रणालियां प्रभावी रूप से चालू नहीं थीं। ऐसे में वाहनों की वास्तविक तैनाती, उनके रूट और संचालन, सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति तथा किए गए कार्य की मात्रा का निष्पक्ष सत्यापन किस आधार पर किया गया। यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है। रवि व्यास ने सवाल उठाया कि यदि वीटीएमएस, जीपीएस, एमआईएस और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड उपलब्ध

नहीं थे, तो संबंधित अवधि के बिलों को प्रमाणित करने, भुगतान की सिफारिश करने, मंजूरी देने तथा उनका ऑडिट करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित ठेकेदारों और मनपा प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है।

2023 की नई निविदा में राशि बढ़ाकर करीब 150 करोड़ की

मीरा-भाईंदर शहर की दैनिक सफाई और कचरा परिवहन का ठेका दो जोन में बांटकर दो कंपनिय को पांच वर्षों के लिए दिया गया है।

जोन-1 में प्रभाग समिति क्रमांक 1, 2 और 3 शामिल हैं, जिसका ठेका मे। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट का जुलाई 2023 में दिया गया। वहीं जोन-2 में प्रभाग समिति क्रमांक 4, 5 और 6 का ठेका मे। कोणाव इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मार्च 2023 में दिया गया। व्यास के अनुसार, वर्ष 2012 में प्रतिदिन करीब 450 टन कचरे की सफाई और परिवहन के लिए वार्षिक निविदा राशि लगभग 39 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2023 तक बढ़कर करीब 90 करोड़ रुपय हो गई। उनका आरोप है कि वर्ष 2023 की नई निविदा में यह राशि बढ़ाकर करीब 150 करोड़ रुपय सालाना कर दी गई। खास बात यह है कि पहले ठेका कंपनी को ही वाहन उपलब्ध कराने होते थे, जबकि नए ठेके में वाहन मनपा द्वारा खरीदकर उपलब्ध कराए गए हैं।

मुद्दा सिर्फ ठेकेदार का नहीं, सार्वजनिक धन का है

मीरा-भाईंदर मनपा में सदन नेता एड. रवि व्यास का कहना है कि मुद्दा केवल ठेकेदार का नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और उसकी निगरानी की पूरी व्यवस्था का है। यदि अनुबंध में अनिवार्य सत्यापन प्रणाली चालू नहीं थी, तो फिर करोड़ों रुपये के भुगतान किस दस्तावेज और किस तकनीकी प्रमाण के आधार पर किए गए, इसकी निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। दोषी ठेकेदार या अधिकारी कोई भी हो, उसकी जवाबदेही तय कर सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

मुंबई के विधायक कितने एक्टिव ?

विधानसभा में सवाल पूछने में 72% की आई गिरावट, कांग्रेस के तीन एमएलए रहे अव्वल...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई के विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सवालों की गुणवत्ता का औसत स्कोर 12वीं विधानसभा में 50 प्रतिशत से गिरकर 15वीं विधानसभा में 33 प्रतिशत हो गया है। साथ ही, इसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस के तीन विधायक ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग में सबसे आगे रहे।

पहले स्थान पर कौन है ?

रिपोर्ट में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल को 82.89 के स्कोर के साथ पहला स्थान मिला, उनके बाद पार्टी के साथी असलम शेख (80.58) और ज्योति गायकवाड़ (80.30) रहे। मुंबई के उन 33 विधायकों में से ये केवल तीन हैं जिन्होंने इस मूल्यांकन में 80 प्रतिशत से अधिक स्कोर किया। ये नतीजे ह्यमुंबईज एमएलए रिपोर्ट कार्ड, 2026ह्व में शामिल थे, जो मुंबई के चुने हुए प्रतिनिधियों के विंटर सेशन 2024 से मॉनसून सेशन 2025 तक के कामकाज का सबूत-आधारित मूल्यांकन है। यह एनालिसिस प्रजा फाउंडेशन ने किया था, जो एक गैर-सरकारी संगठन है और नागरिक मुद्दों तथा जवाबदेह शासन पर काम करता है।

अब तक कितने विधायकों ने सवाल पूछे?

पिछले कुछ वर्षों में मुंबई के विधायकों की ओर से पूछे गए

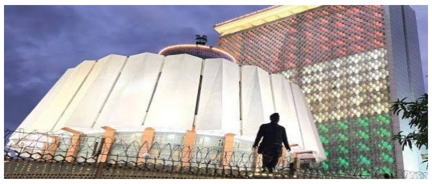

सवालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। 15वीं विधानसभा के दौरान (विंटर सेशन 2024 से मॉनसून सेशन 2025 तक) इन 33 विधायकों ने 2,213 सवाल पूछे। यह संख्या 12वीं विधानसभा की इसी अवधि (विंटर 2009 से मॉनसून 2010 तक) में पूछे गए 7,955 सवालों की तुलना में 72 प्रतिशत कम है। 15वीं विधानसभा में इन 33 विधायकों का कुल औसत स्कोर 55 रहा, जबकि 12वीं विधानसभा में यह 61 था। रिपोर्ट के अनुसार, 14वीं विधानसभा में औसत स्कोर गिरकर 54 हो गया था, जिसके बाद 15वीं विधानसभा में इसमें मामूली सुधार देखा गया।

मुंबईकर ध्यान दें! 27 सितंबर तक भूलकर भी साथ न रखें ये सामान... वरना पुलिस करेगी सीधी कार्रवाई!

मुंबई : मुंबई में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हथियारों और अन्य खतरनाक वस्तुओं को साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस का यह आदेश 29 अगस्त से 27 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके

तहत तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य वस्तुएं साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से अनुमति मिलने पर इन वस्तुओं को साथ रखने की छूट दी जा सकेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

त्योहारों के दौरान सुरक्षा पर जोर

मुंबई में पांच सितंबर को दही हांडी उत्सव मनाया जाएगा और 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव 14 सितंबर से शुरू होगा। इन बड़े आयोजनों के दौरान शहर में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे में पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ये कदम उठाए हैं। आदेश के तहत खतरनाक रसायनों और विस्फोटक पदार्थों को रखने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा पत्थर, मिसाइल या मिसाइल दागने वाले उपकरणों के भंडारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। मुंबई पुलिस के आदेश में सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों, शवों, आकृतियों, चित्रों या पुतलों के प्रदर्शन को लेकर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे सार्वजनिक बयान, गीत या संगीत भी प्रतिबंधित किए गए हैं, जिन्हें किसी पुलिस अधिकारी की राय में शालीनता या नैतिकता के खिलाफ माना जाए और जिनसे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आदेश खत्म होने के बाद भी कार्रवाई संभव

अधिकारी ने बताया कि 27 सितंबर को प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बावजूद इस दौरान हुए उल्लंघनों की जांच या कानूनी कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।

नागपुर: रात में बंद दुकान, सुबह गायब मिला सामान; कड़क चाय वाला दुकान में मोबाइल समेत इतने हजार की हुई चोरी

नागपुर : नागपुर के छत्रपति चौक के पास साई मंदिर के सामने स्थित ह्यकड़क चाय वालाह्व दुकान में 21 अगस्त की सुबह चोरी होने से हड़कंप मच गया। दुकान संचालक बालाजी रंगनाथ फड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 20 अगस्त की रात करीब 11 बजे दुकान बंद की थी। इसके बाद 21 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे जब वे दुकान खोलने पहुंचे, तो दुकान में चोरी होने का संदेह हुआ। जांच करने पर दुकान से नकदी, मोबाइल फोन, बैग और अन्य सामान गायब मिला। घटना के बाद उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की है।

कैसे दुकान में घुसे चोर ?

दुकान की जांच करने पर कैश काउंटर में

रखी करीब 9 से 10 हजार रुपये की नकदी, Oppo A53 मोबाइल फोन, एक बैग और अन्य सामान गायब मिला। चोरी हुए सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 हजार रुपये बताई गई है। शिकायत के अनुसार, चोरों ने 21 अगस्त की सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच दुकान का शटर ऊपर उठाकर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान खोलने पहुंचे संचालक बालाजी रंगनाथ फड को सामान गायब मिलने पर चोरी का पता चला। घटना के बाद उन्होंने धंतोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को जल्द पकड़कर चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की है।

नागपुर में बढ़ती चोरियों से बढ़ी चिंता

बालाजी रंगनाथ फड ने पुलिस को बताया कि चोरी हुए Oppo A53 मोबाइल फोन में इरठछ का सिम कार्ड लगा हुआ था, जिसका नंबर 7588364292 है। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर संदिग्ध आरोपी को जल्द पकड़ने और चोरी हुआ मोबाइल, नकदी व अन्य सामान बरामद कराने की मांग की है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपी के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है।

महाराष्ट्र की सेल्फ-फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी में बनेगा मराठी भाषा विभाग, चंद्रकांत पाटिल ने दिए निर्देश...

महाराष्ट्र : राज्य की सभी सेल्फ-फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी में मराठी भाषा विभाग स्थापित करने के निर्देश उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने दिए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने के साथ विद्यार्थी हित के विभिन्न उपक्रम प्रभावी ढंग से चलाने को कहा। डॉ. होमी भाभा राज्य विश्वविद्यालय में चंद्रकांतदादा पाटिल की अध्यक्षता में राज्य की सेल्फ-फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटी के प्रायोजक मंडल के अध्यक्षों और कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 के क्रियान्वयन, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कामकाज और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की गई।

उच्च शिक्षा में मराठी को बढ़ावा

बैठक में राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति के तहत प्रशिक्षण और चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में यूनिवर्सिटी की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली गई। मंत्री ने सकल नामांकन अनुपात और स्नातक उपाधि पूर्णता अनुपात से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के संकेतस्थल पर दर्ज करने तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सूचना फलक पर आवश्यक जानकारी अद्यतन रखने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर

पाटिल ने यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद और राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही राष्ट्रीय संस्थागत क्रम निर्धारण में यूनिवर्सिटी की भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रवेशित विद्यार्थियों के अपार पहचान पत्र बनाने और उनके शैक्षणिक जमा खाते से शत-प्रतिशत जोड़ने को कहा। विद्यार्थियों का राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संबंधित संकेतस्थलों पर पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

उच्च शिक्षा में मराठी को बढ़ावा देने की तैयारी

कम आय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर देने के लिए 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत शुल्क में छूट देने के विषय पर भी चर्चा हुई। पाटिल ने यूनिवर्सिटी से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए विद्यार्थी हित में आवश्यक कदम उठाने को कहा। बैठक में यूनिवर्सिटी के विभिन्न वैधानिक मंडलों के कामकाज की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी ने यूनिवर्सिटी को वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

रेत से भरे हाइवा ने 8 वर्षीय छात्रा को कुचला, मौके पर मौत; बड़ी बहन घायल...

छत्रपति संभाजीनगर : छत्रपति संभाजीनगर के अंबेलोहल से विटावा की ओर जा रहे रेत से भरे तेज रफ्तार हाइवा ने सड़क पार कर रही आठ वर्षीय छात्रा को कुचल दिया। मंगलवार को विटावा-एकलहेरा मार्ग पर हुए इस दर्दनाक हादसे में आरुषी कृष्णा तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसकी 16 वर्षीय बड़ी बहन नंदिनी तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार, कृष्णा तिवारी की आठ वर्षीय बेटी आरुषी विटावा स्थित ग्लोबल किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। मंगलवार को वह रोज की तरह स्कूल गई थी। दोपहर में छुट्टी होने के बाद वह बस से घर लौट रही थी। बस से उतरने के बाद वह सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान अंबेलोहल की ओर से आ रहे बिना नंबर के तेज रफ्तार हाइवा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।

विटावा-एकलहेरा मार्ग पर दर्दनाक हादसा

हाइवा का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरुषी को लेने पहुंची उसकी बड़ी बहन नंदिनी भी हादसे में घायल हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाइवा चालक की पिटाई कर वाहन पर पथराव कर तोड़फोड़ की। चालक किसी तरह भीड़ से बचकर खेतों के रास्ते फरार हो गया। सूचना मिलते ही एमआईडीसी वालुज पुलिस और यातायात शाखा की टीम मौके पर पहुंची। घायल नंदिनी को उपचार के लिए घाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर छत्रपति संभाजीनगर मनपा का डबल एक्शन, एक ही व्यापारी पर दूसरी बार भरा इतनें हजार दंड!

छत्रपति संभाजीनगर : राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। मनपा आयुक्त अमोल येडगे के आदेश तथा उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे की निगरानी में नागरिक मित्र दल ने शहर में विशेष अभियान चलाकर कुल 1,340 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया।

पहले भी लग चुका है जुमार्ना

प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने के मामले में ह्यएस.के. प्लास्टिकह्न के संचालक संजय आसाराम कटारे के खिलाफ मनपा ने दूसरी बार कार्रवाई की। इससे पहले 23 अप्रैल को प्रतिष्ठान से 560 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया था और 25 हजार रुपये का जुमार्ना वसूला गया था। इसके बावजूद

दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने और बिक्री करने का मामला सामने आया। मंगलवार को मनपा के विशेष अभियान के दौरान फिर प्रतिष्ठान की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक पर दोबारा 25 हजार रुपये का दंड लगाया गया। मनपा ने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन करने पर अब पुलिस कार्रवाई और प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।

नागरिक मित्र दल ने की कार्रवाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ छत्रपति संभाजीनगर मनपा की कार्रवाई नागरिक मित्र दल ने की। अभियान में देविदास सुसर, जनार्दन सांगले और बालाजी साबले के साथ मनपा जवान किशोर नाडे तथा आनंद चावन्या शामिल रहे। टीम ने जांच के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर संबंधित प्रतिष्ठान पर दंडात्मक कार्रवाई की।

मनपा प्रशासन ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब केवल जुमार्ना लगाकर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर उसे सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। मनपा ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्लास्टिक बंदी से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें और प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टॉक, उपयोग या बिक्री न करें। प्रशासन ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा जताई है।

मीरा-भाईंदर मनपा में सेवा नियमों का प्रस्ताव दोबारा खारिज, प्रमोशन का इंतजार बढ़ा, कर्मचारियों में भारी आक्रोश

मीरा-भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के सैकड़ों कर्मचारियों के करियर को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रशासन की ओर से सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन के लिए लाया गया महत्वपूर्ण प्रस्ताव महासभा में पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया है। सदन में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही मनपा के प्रशासनिक गलियारों में कर्मचारियों का गुस्सा और असंतोष खुलकर सामने आने लगा है।

सालों से एक ही पद पर अटके हैं कर्मचारी

इस फैसले ने उन कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो पिछले कई सालों से एक ही टेबल पर काम कर रहे हैं। महानगर पालिका के भीतर लिपिकीय और तृतीय श्रेणी के पदों पर बैठे कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। नियमानुसार आवश्यक सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद उन्हें वरिष्ठ पदों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विडंबना यह है कि विभाग के कई कर्मचारी तो प्रमोशन का

इंतजार करते-करते ही रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनके सेवाकाल में उन्हें जायज हक नहीं मिल सका।

ऐसा नहीं है कि यह प्रस्ताव पहली बार आया था। प्रशासन ने इससे पहले जुलाई में भी इसे सदन के पटल पर रखा था, लेकिन तब पदोन्नति प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायत कर इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली गई थी। उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल ने इस बार प्रस्ताव खारिज होने की मुख्य वजह बताते हुए कहा कि कुछ पार्षदों और कर्मचारियों की तरफ से शिकायतें मिली थीं कि इस नए बदलाव से कुछ विशेष लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रस्ताव को दोबारा नामंजूर कर दिया गया। बार-बार प्रस्ताव लटकने से पैदा हुए भारी असंतोष को देखते हुए अब प्रशासन इस पर फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। उपमहापौर के अनुसार, अब इस पूरे मसौदे का गहन अध्ययन किया जाएगा। इसमें सभी जरूरी कानूनी सुधार और व्यापक प्रावधान जोड़े जाएंगे ताकि किसी भी स्तर पर पक्षपात न हो सके।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

शिक्षा कैसी हो?

कई पीढियों तक उच्च शिक्षा का उद्देश्य अपेक्षाकृत स्पष्ट रहा- पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, नौकरी प्राप्त करो और करियर बनाओ। इस व्यवस्था ने समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज दुनिया जिस गति से बदल रही है, उसमें केवल डिग्री आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं रह गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, बदलती अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और रोजगार के बदलते स्वरूप ने शिक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। आज के विद्यार्थी को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करना है जिसमें उसके सामने नए प्रकार के काम, नई तकनीकें और लगातार बदलती परिस्थितियां होंगी। इसलिए अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि हम बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाएं? बड़ा प्रश्न यह है कि बदलती दुनिया के लिए हमारी उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हिमाचल प्रदेश के लिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। हमें दूसरे राज्यों या देशों के मॉडल की नकल करने के बजाय अपनी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप उच्च शिक्षा की अपनी दिशा तय करनी होगी। परंपरागत व्यवस्था में शिक्षा को प्रायः ज्ञान, परीक्षा और डिग्री के आधार पर समझा जाता रहा है। डिग्री का महत्व आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब केवल डिग्री को शैक्षणिक सफलता का अंतिम प्रमाण मानना पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य की शिक्षा में ज्ञान के साथ चिंतन, कौशल, चरित्र, अनुभव और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का विकास भी आवश्यक है।

उच्च शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसे युवा तैयार करना होना चाहिए जो केवल नौकरी खोजने वाले न हों, बल्कि समस्याओं को समझ सकें, समाधान खोज सकें, नई परिस्थितियों में सीख सकें और आवश्यकता पड़ने पर नए अवसर भी पैदा कर सकें। यही अंतर नौकरी की तैयारी और जीवन तथा करियर के लिए क्षमता निर्माण के बीच है। आज का विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक और परीक्षा तक सीमित नहीं रह सकता। उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़ना होगा। उसे परियोजनाओं, शोध, इंटर्नशिप, सामुदायिक कार्य, उद्यमिता और व्यावहारिक अनुभवों से सीखना होगा। आज सूचना की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, डिजिटल पुस्तकालय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से विद्यार्थी कुछ ही क्षणों में बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

editor@rokthoklekhani.com
+91 9987775650
Faisal Shaikh @faisalrokthok
ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

या तो मराठा जीतेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा...

मनोज जरांगे पाटील की सरकार को चेतावनी... बोले- अब यह अंतिम संघर्ष

मुंबई : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर पूरी तरह गरमा गई है। जालना जिले से मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटील ने राज्य सरकार को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब मराठा समाज को मीठी-मीठी बातों से गुमराह करने के दिन पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने सरकार के सामने अपनी अंतिम समय-सीमा रखते हुए कहा है कि सरकार 28 अगस्त तक अपना रुख पूरी तरह साफ कर दे, क्योंकि 29 अगस्त से शुरू होने वाला निर्णायक आंदोलन अब किसी भी परिस्थिति में टलने वाला नहीं है। मनोज जरांगे पाटील ने इस बार की लड़ाई को निर्णायक और अंतिम संघर्ष करार दिया है। उन्होंने मीडिया से खुलकर बातचीत करते हुए कहा, इस अंतिम लड़ाई में या तो मराठा समाज 100 प्रतिशत जीतेगा या मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। यह बयान देकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वे पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं।

चर्चा के बहाने केवल समय निकालना चाहती है सरकार

यह तीखा बयान तब आया जब राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जालना के अंतरवाली सराटी में जरांगे पाटील से मुलाकात करने पहुंचने वाला था। जरांगे पाटील ने सरकार की 'बार-बार प्रतिनिधिमंडल भेजने'की नीति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि हालांकि प्रतिनिधिमंडल आएगा तो वे शिष्टाचार के नाते उसकी बात जरूर सुनेंगे, लेकिन सरकार चर्चा के बहाने केवल समय निकालना चाहती है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले तीन वर्षों में कई सरकारें आईं और गई, और मराठा समाज ने उनके हर आश्वासन का पूरा सम्मान किया, परंतु अब और अधिक अन्याय सहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि सरकार के प्रतिनिधिमंडल केवल समय काटने के लिए चर्चा का नाटक कर रहे हैं।

कुणबी रिकॉर्ड और गजट लागू करने की अड़िग मांग

मनोज जरांगे पाटील ने अपनी मांगों की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि जिन भी मराठों के कुणबी रिकॉर्ड मिल चुके हैं, उन्हें सरकार को तुरंत प्रमाणपत्र और उनके संवैधानिक अधिकार सौंपने होंगे; इसे अब किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित गजट को भी तुरंत प्रभाव से लागू करने की अपनी पुरानी मांग को मजबूती से दोहराया है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि 28 अगस्त तक इस दिशा में कोई ठोस और आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया, तो 29 अगस्त का आंदोलन शुरू होकर रहेगा। इस दौरान जरांगे पाटील ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भुजबल को अब अच्छी तरह से यह समझ आ चुका है कि मराठा समाज के कितने रिकॉर्ड मिले हैं और इससे जुड़ी संवैधानिक व्यवस्था क्या है। उन्होंने आगे कहा कि भुजबल यह भी भली-भांति जान चुके हैं कि मराठा समाज का विरोध करने से उन्हें कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

मुंबई : 250 करोड़ की जमीन, 128 फ्लैट और वीआईपी मालिक...

मुंबई के रुस्तमजी क्राउन क्यों चला हथौड़ा

मुंबई : मुंबई की सिविक बॉडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी ने सोमवार को प्रभादेवी स्थित लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स 'रुस्तमजी क्राउन'के कुछ फ्लैट्स में कथित तौर पर बिना मंजूर के किए गए बदलावों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. खास बात तो ये है कि यह कार्रवाई आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर की शिकायतों के बाद की गई. डौंडकर का आरोप था कि कुछ निवासियों ने कॉमन एरिया पर कब्जा करके उस एरिया को अपने फ्लैट में मिला लिया है. साथ ही, एफएसआई की गणना में जो जगह शामिल नहीं है, उनका भी कथित तौर पर गलत इस्तेमाल किया गया. डौंडकर का कहना है कि कुछ फ्लैट्स में 450 से 800 वर्ग फीट की कॉमन जगह को भी शामिल किया गया है. इसकी बाजार में मौजूदा कीमत लगभग 2.25 करोड़ से 2.50 करोड़ तक है. बीएमसी की टीम ने इन शिकायतों पर संज्ञान लिया. और सोमवार को पुलिस सुरक्षा के बीच तीन फ्लैट्स में तोड़फोड़ की गई. इस कार्रवाई के लिए 15 मजदूरों और बीएमसी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम को तैनात किया गया था. यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 354ए और महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट की धारा 53(1) के तहत जारी किए गए. बीएमसी का कहना है कि आगे की कार्रवाई तय प्रक्रिया के तहत होगी. इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. रुस्तमजी क्राउन के ए और बी विंग बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों में ही 63 मंजिलें हैं. जबकि सी विंग का निर्माण कार्य अभी चल रहा है.

मुंबई से मिली तीन नाबालिग लड़कियां, 10 अगस्त से थीं लापता; एक शख्स गिरफ्तार...

मुंबई: फरीदकोट शहर से करीब दो सप्ताह पहले 10 अगस्त 2026 से लापता हुई तीन नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मुंबई से ढूंढ निकाला है। पुलिस टीम छात्राओं को फरीदकोट लेकर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि तीनों छात्राएं फरीदकोट से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थीं।

वहां उन्हे एक युवती मिली जोकि इन छात्राओं को अपने झांसे में लेकर मुंबई ले गई और बाद में उन्हें आशीष नामक एक व्यक्ति के पास छोड़ दिया। पुलिस ने आशीष को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर फरीदकोट लाया जा रहा है जबकि छात्राओं को दिल्ली से मुंबई ले जाने वाली युवती की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों को फरीदकोट लाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि छात्राओं को मुंबई ले जाने के पीछे उनकी वास्तविक मंशा क्या थी। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी बड़े रैकेट की संलिप्तता की संभावना को भी जांच के दायरे में रख रही है। थाना सिटी-2 के एसएचओ अकलप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने 'ूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी जांच के आधार पर छात्राओं की मुंबई में लोकेशन का पता लगाया था। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों छात्राओं को सकुशल ढूंढ लिया। एसएचओ ने बताया कि मामले में गिरफ्तार आरोपी युवक को फरीदकोट लाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर छात्राओं को मुंबई ले जाने की पूरी कहानी सामने आने की संभावना है। पुलिस को इस घटनाक्रम में किसी बड़े गिरोह या रैकेट की भूमिका होने की भी आशंका है।

नई दिल्ली : कांग्रेस में शकील अहमद का कड़ा वार: राहुल गांधी को बताया "डरपोक और असुरक्षित", सियासी गलियारों में आया भूचाल

नई दिल्ली : पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शकील अहमद ने शनिवार को राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित नेता करार देते हुए आरोप लगाया कि वह केवल उन युवा नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो पार्टी में उनका गुणगान करते हैं यानी उनकी चापलूसी करते हैं। शकील अहमद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। वह तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं। वह 2000 से 2003 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। अहमद ने कहा कि राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में खुद को असहज महसूस करते हैं, खासकर जिनकी जनता पर अच्छी पकड़ है। इसलिए वह सिर्फ उन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने राहुल को तानाशाही और गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ सहयोगियों की बात नहीं सुनते और ऐसा सोचते है कि पार्टी अपनी राष्ट्रीय

मौजूदगी के कारण दूसरे स्थान से नीचे नहीं जा सकती। पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब अमेठी हार गए थे। उन्होंने कहा कि वह अपने पूर्वजों और परिवार की परंपरागत सीट को भी अपने रवैये के कारण नहीं जीत सके। अहमद ने कहा- ''राहुल गांधी एक कायर और असुरक्षित व्यक्ति हैं। वह किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति या बड़ा सार्वजनिक रुतबा रखने वाले व्यक्ति के सामने बॉस फीलिंग नहीं महसूस करते। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ असहज होते हैं और इसलिए तानाशाह और गैर-लोकतांत्रिक हैं।'' वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि उन्हें बिहार में एसआइआर के दौरान किसी का नाम मतदाता सूची से हटाने का दावा नहीं मिला।

शकील ने उजागर की कांग्रेस नेता की असलियत : भाजपा

भाजपा ने अहमद के बयान का हवाला दे राहुल पर जोरदार हमला बोला। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा- ''शकील अहमद ने राहुल गांधी की असलियत को उजागर किया है। राहुल गांधी दिखाते हैं कि वह सबसे सहिष्णु और लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वह सबसे तानाशाही व्यक्ति हैं और उनके पास वही आपातकालीन मानसिकता है जो इंदिरा गांधी के पास थी।''

आगरा: 13 साल पहले कोर्ट में खुद को बताया "मृत"

अब स्कूटर चलाते मिला; आरोपी को भेजा गया जेल

आगरा: फर्जी वसीयत के मामले में कार्रवाई से बचने के लिए करीब 13 साल पहले खुद को मृत घोषित करने वाला आरोपी आखिरकार अदालत में पहुंच गया। आरोप है कि उसने अदालत में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर खुद को मृत साबित करने की कोशिश की थी। अब जब मामले की सच्चाई सामने आई तो आरोपी ताराचंद शर्मा ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश दिए। मामला वर्ष 1999 से अदालत में विचाराधीन था। वादी विद्या देवी की ओर से चुन्नीलाल गोयल, रामकुमार वर्मा, रोशनलाल वर्मा और ताराचंद शर्मा के खिलाफ फर्जी वसीयत तैयार करने का परिवाद दाखिल किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान चुन्नीलाल गोयल और रोशनलाल वर्मा की मृत्यु हो गई। इसी बीच

आरोप है कि ताराचंद शर्मा ने वर्ष 1998 का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल कर खुद को मृत घोषित कर दिया। वर्ष 2013 में अदालत ने ताराचंद को मृत मानते हुए उसके खिलाफ चल रहा मुकदमा बंद कर दिया।

12 साल बाद स्कूटर चलाते मिला "मृत" आरोपी

मामले में नया मोड़ नवंबर 2025 में आया। वादी ने ताराचंद शर्मा को गांधी नगर में स्कूटर चलाते हुए देख लिया। संदेह होने पर वादी ने उसकी तस्वीर भी खींच ली। इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए अदालत को गुमराह करने का मामला सामने आया।

वादी ने अधिवक्ता समीर भटनागर के माध्यम से पुलिस से शिकायत की। पुलिस से कार्रवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। अदालत के आदेश पर 9 मार्च को तत्कालीन थाना प्रभारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत के आदेश के बाद थाना न्यू आगरा पुलिस ने मामले की जांच की। एसआई मधुर चतुर्वेदी की जांच आख्या के मुताबिक ताराचंद शर्मा अपने घर पर जीवित मिले।

पुलिस जांच में उनके बेटे आशुतोष शर्मा ने भी बयान दिया कि उनके पिता जीवित हैं और घर पर ही रहते हैं। वह कभी-कभी स्कूटर से बाहर भी जाते हैं। पुलिस ने ताराचंद शर्मा और उनके बेटे की तस्वीरें भी लीं, जिन्हें अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया।

मैनपुरी में सेना के जवान ने डीएम से लगाई गुहार; दबंग कर रहे जमीन पर अवैध कब्जा, दिलाएं न्याय

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सेना के जवान की जमीन पर दबंगों के कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले में जवान ने डीएम से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। असम में तैनात भारतीय सैनिक ने अपनी पैतृक जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप लगाया है। सैनिक का कहना है कि हम छुट्टी लेकर घर आए हैं, लेकिन दबंगों से अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। मैनपुरी डीएम ऑफिस पहुंच कर सैनिक ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला करहल थाना क्षेत्र के नगला जंगी गांव का है।

क्या है मामला?

करहल के नगला जंगी गांव के रहने वाले सत्यपाल सिंह सेना में जवान हैं। अभी उनकी पोस्टिंग असम में है। उन्होंने डीएम को सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग उनकी खेती की जमीन पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। सत्यपाल सिंह का कहना है कि हम देश की सीमा पर सेवा देते हैं। चीन बॉर्डर पर भी सेवा दी है। छुट्टी लेकर गांव आने के बाद भी अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा हूं। जवान सत्यपाल सिंह ने करहल तहसील मुख्यालय पर संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की थी। अब डीएम ऑफिस पहुंच कर भी शिकायत की है। सत्यपाल सिंह ने कहा कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी जमीन सुरक्षित नहीं है। डीएम ने शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

डीएम ने जांच के दिए आदेश

जवान सत्यपाल सिंह का आरोप है कि नगला जंगी उरथान गांव में उनकी खेती की जमीन है। इस जमीन पर राजेंद्र सिंह, पंकज और सुभास अकबरी के कब्जे का आरोप जवान ने लगाया। जवान की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम के आदेश पर करहल राजस्व विभाग टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

शाहजहांपुर: 'बराबर बंटेगी कमाई', करप्शन की 'कसम' खाते पार्षदों का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंसछ का दावा करती है, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ नुमाइंदे इन दावों की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसका एक सनसनीखेज वीडियो शाहजहांपुर से सामने आया है. यहां शाहजहांपुर नगर निगम के कुछ पार्षदों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर हाथ में जल लेकर भ्रष्टाचार की कमाई (कमीशन) को आपस में बराबर बांटने की 'शपथछ लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है.

हाथ में जल... और 'कमीशनछ बांटने की कसम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नगर निगम के कुछ पार्षद एक जगह इकट्ठा हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग बिल्कुल उसी तरह हाथ में जल लेकर कसम खा रहे हैं, जैसे किसी पवित्र कार्य के लिए संकल्प लिया जाता है. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ये पार्षद नगर निगम से होने वाली 'आयछ (कथित भ्रष्टाचार/कमीशन) को सभी के बीच बराबर बांटने की बात कह रहे हैं. हद तो तब हो गई जब वीडियो में एक पार्षद खुलेआम यह धमकी देता और गाली बकता सुनाई देता है कि ''यदि कोई इस व्यवस्था (बराबर बंटवारे) को नहीं मानेगा तो...''.

वित्त मंत्री के गढ़ में सुशासन पर उठे बड़े सवाल

इस वीडियो के सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर तो गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा भी गरमा गया है. दरअसल, शाहजहांपुर नगर क्षेत्र से स्थानीय विधायक कोई और नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री (वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री) सुरेश कुमार खन्ना हैं. ऐसे में इतने कद्दावर मंत्री के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों का इस तरह करप्शन की 'कसमछ खाना व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है.

क्या होगी इस वायरल 'शपथछ की जांच?

भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली सरकार के सामने अब यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह वीडियो असली है, तो हाथ में जल लेकर खाए जा रहे इस 'कमीशन के संकल्पछ का मास्टरमाइंड कौन है? यह 'नगर निगम की आयछ आखिर किस टेंडर या घोटाले की तरफ इशारा कर रही है? फिलहाल, जनता और विपक्ष अब इस वायरल वीडियो की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पार्षदों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत, साउथ चाइना सी में फ्यूचर प्लान तैयार

US के लिए चुनौती !

बीजिंग: विवादित दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह में चीन की नई सैन्य गतिविधियों ने वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों की चिंता बढ़ा दी है। रॉयटर्स के अनुसार, इस क्षेत्र के एंटेलोप रीफ के पास स्थित एक छोटे से द्वीप पर नया निर्माण कार्य देखा गया है, जिसे चीन का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य बेस माना जा रहा है।

सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यागोंग द्वीप पर हो रहे इस त्रि-आयामी निर्माण के अंतिम उद्देश्य का अभी सटीक आकलन करना जल्दबाजी होगी। हालांकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह एंटेलोप रीफ पर भविष्य के सैन्य प्रतिष्ठानों को मजबूती देने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी रडार सुविधा की शुरूआत हो सकती है। चीन के इस आक्रामक कदम से क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और गहराने की आशंका है।

दक्षिण चीन सागर में चीन की नई चाल

विवादित दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह में एंटेलोप रीफ के पास एक छोटे से द्वीप पर नए निर्माण देखे गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चीन यहां अपना सबसे बड़ा सैन्य बेस बना रहा है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यागोंग द्वीप पर हो रहे इस त्रि-आयामी निर्माण के अंतिम उद्देश्य का अभी सटीक आकलन करना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह एंटेलोप रीफ पर भविष्य के प्रतिष्ठानों का समर्थन करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी रडार सुविधा की शुरूआत हो सकती है। कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें प्रदान करने वाली कंपनी वेंटोर ने 17 अगस्त को इस क्षेत्र की नवीनतम तस्वीर ली थी। पिछली तस्वीरों के आधार पर कंपनी ने बताया कि यहां निर्माण कार्य मार्च और अप्रैल में शुरू हुआ था। वेंटोर के एक प्रवक्ता ने कहा कि यद्यपि इन इमारतों का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यागोंग रीफ पर कई संरचनाएं दक्षिण चीन सागर में अन्य जगहों पर देखी गई सैन्य रडार/प्रारंभिक चेतावनी सुविधाओं से काफी मिलती-जुलती हैं। संभवतः ये पास के एंटेलोप रीफ के सैन्य कार्यों से जुड़ी हैं।

एंटेलोप रीफ का बढ़ता सैन्यीकरण

रॉयटर्स ने पिछले सप्ताह अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने एंटेलोप रीफ पर निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया है। यह स्थिति दक्षिण चीन सागर को चीन और अमेरिका के बीच एक बढ़ते सैन्य अखाड़े के रूप में उजागर करती है। ताइवान को लेकर भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

राफेल का सीक्रेट कोड क्रैक करने की फिराक में चीन?

ड्रैगन ने तैयार किया जे-16 वाला प्लान

काहिरा: चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स के जे-16 फाइटर जेट्स ने मिस्र के राफेल विमानों के साथ ऐतिहासिक हवाई युद्ध का अभ्यास किया। यह मुकाबला मिस्र में चल रहे ''ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026'' संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान हुआ। इससे चीनी वायुसेना को उन विमानों के खिलाफ सीधे प्रशिक्षण का मौका मिल गया जिनका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना भी करती है।

राफेल ५२ जे-16 फाइटर जेट

अभ्यास के पहले दिन अलग-अलग फाइटर जेट्स के बीच वन-ऑन-वन मुकाबले पर फोकस किया गया। चीनी और मिस्र के पायलटों ने एक-दूसरे के लड़ाकू विमानों की क्षमताओं की जानकारी शेयर की। उन्होंने उड़ान सुरक्षा नियमों, एयरस्पेस प्रक्रियाओं, टेक-ऑफ और लैंडिंग प्रोटोकॉल और इमरजेंसी के समय में कार्रवाई पर चर्चा की। पीएलए एयर फोर्स का कहना है कि यह अभ्यास आगे टू-ऑन-टू हवाई मुकाबलों और फिर अधिक जटिल संयुक्त अभियानों तक बढ़ेगा।

चीन को कितना फायदा?

इस अभ्यास का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जे-16 को पहली बार राफेल के साथ सीधे सिम्युलेटेड कॉम्बैट का अनुभव मिल रहा है। चीन अक्सर अपने विमानों की ट्रेनिंग अपने ही प्लेटफॉर्म के खिलाफ करता है। पश्चिमी डिजाइन वाले राफेल जैसे विमान के खिलाफ सुनियोजित हवाई युद्ध का मौका बहुत कम मिलता है। मिस्र के राफेल चीनी पायलटों के लिए बेहतरीन लक्ष्य साबित हो रहे हैं। इससे वे राफेल की उड़ान खूबियों, मुड़ने की क्षमता और रणनीतिक व्यवहार को नजदीक से समझ सकते हैं। चीनी एविएशन विशेषज्ञ वांग यानान ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि यह अभ्यास चीन को राफेल के बारे में जानने का मौका दे रहा है, क्योंकि भारत और मिस्र इसके मुख्य ऑपरेटर हैं। इस युद्ध अभ्यास से पीएलए को यह समझने में मदद मिलेगी कि राफेल अलग-अलग युद्ध में कैसे व्यवहार करता है और जे-16 पायलट उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इससे चीनी प्रशिक्षकों और योजनाकारों को वास्तविक दुनिया का प्रशिक्षण संदर्भ भी मिलेगा।

भारत रख रहा सटीक नजर?

भारत इस युद्ध अभ्यास पर बारीकी से नजर रख रहा है। राफेल के खिलाफ नकली लड़ाई का अनुभव पीएलए एयर फोर्स को उस प्लेटफॉर्म का अध्ययन करने का मौका दे रहा है, जिसका सामना भविष्य में भारत-चीन तनाव में हो सकता है। हालांकि मिस्र के राफेल हथियार, सेंसर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन में भारत के राफेल जैसे नहीं हैं। इसलिए इसे भारत-चीन हवाई लड़ाई का सीधा सिमुलेशन नहीं माना जा सकता। फिर भी यह चीन को महत्वपूर्ण

पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में तुर्की की एंट्री, एर्दोगन का ''इस्लामिक कैम्पेन'',

भारत के लिए कितना खतरा?

अंकारा : पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध करना और बांग्लादेश को ''मक्का डिफेंस पैक्ट'' में शामिल करने की तुर्की की कोशिश कुछ और नहीं बल्कि भारत के पड़ोस को ''इस्लामिक रंग'' में रंगने की कोशिश है। तुर्की की इन चालों पर भारत को घबराने की नहीं बल्कि नजर रखने की जरूरत है।

सेंटर फॉर जियोपॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटजिक स्टडीज की फेलो डॉ. इंद्राणी तालुकदार ने लिखा है कि भारत के लिए अंकारा के साथ रिश्तों में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने लिखा है कि 2020 के बाद खासकर ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बाद और ग्रीस और साइप्रस जो तुर्की के पुराने दुश्मन रहे हैं उनके साथ बढ़ते रिश्तों के जरिए पूर्वी भूमध्य सागर में नई दिल्ली की बढ़ती सक्रियता के कारण तुर्की-पाकिस्तान-सऊदी अरब-बांग्लादेश का यह नया रणनीतिक गठजोड़ कई तरह की चुनौतियां पेश करता है।

हालांकि उनका ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। भारत ने जरूर ग्रीस और साइप्रस से सैन्य संबंध बनाए हैं लेकिन ऐसा पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिलने के बाद शुरू किया गया है।

बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है तुर्की?

बांग्लादेश को अगर तुर्की पाकिस्तान और सऊदी वाले सैन्य गठबंधन में शामिल करता है तो भारत को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तुर्की जरूर भारत की रणनीतिक घेराबंदी करने की कोशिश करेग। लेकिन ऐसा करना उसके लिए अत्यंत मुश्किल होगा और जितने संसाधन की जरूरत उसे होगी उतना जुटाना तुर्की के लिए संभव नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ढाका ने पारंपरिक रूप से भारत, अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों के साथ संबंध बनाकर रणनीतिक संतुलन बनाए रखा है। लेकिन घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक दबाव और सुरक्षा सहयोगियों में विविधता लाने की इच्छा ने बांग्लादेश को दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते संबंध इसी विविधता का प्रमाण हैं।

हालांकि बांग्लादेश अभी मक्का समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है लेकिन इसमें शामिल होने की उसकी इच्छा यह दशार्ती है कि वह भारत जैसे अपने करीबी और मित्र पड़ोसी देशों पर पारंपरिक निर्भरता से परे सुरक्षा सहयोग की संभावनाओं को तलाशने को तैयार है। यदि बांग्लादेश औपचारिक रूप से मक्का फ्रेमवर्क से जुड़ता है चाहे पर्यवेक्षक या भागीदार के रूप में ही क्यों न हो तो इससे प्रभावी रूप से तुर्की की रणनीतिक उपस्थिति भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंच जाएगी जो इस क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करेगी।

डॉ. इंद्राणी तालुकदार का कहना है कि भारत लंबे समय से दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव वाला स्वाभाविक क्षेत्र मानता रहा है जिसका आधार भौगोलिक निकटता, आर्थिक और सांस्कृतिक निर्भरता और सुरक्षा संबंध हैं। तुर्की-पाकिस्तान-सऊदी अरब-बांग्लादेश का सुरक्षा गठबंधन भले ही यह ढीले ढांचे वाला हो भारत के पड़ोस में एक बाहरी और विचारधारा से प्रेरित ताकत को लाकर भारत की इस प्रधानता को चुनौती देता है। खासकर इसलिए क्योंकि अंकारा और इस्लामाबाद ने बार-बार कश्मीर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भारत की नीतियों की आलोचना की है। बांग्लादेश में तुर्की और पाकिस्तान की गहरी रक्षा उपस्थिति से भारत के पूर्वी हिस्से के पास सैन्य प्रशिक्षण, हथियारों की बिक्री, खुफिया सहयोग और राजनीतिक समन्वय के नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत पहले से ही अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर जटिल सुरक्षा हालात से जूझ रहा है। ऐसे में नई दिल्ली की पहले से ही मुश्किलों भरी पूर्वी सीमा पर नई चुनौतियों के आने से भारत के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और जटिल हो सकती है।

''भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान भुखमरी झेल रहा'', मौलाना डीजल ने शहबाज सरकार को घेरा

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कट्टर राजनीतिक दल जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के आर्थिक विकास का जोरदार नारा दिया है। इन्हें मलेशियाई डीलर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक बदहाली का जिक्र करते हुए सही सलामत अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गंभीर आंतरिक उद्घाटन का सामना कर रहा है। ऐसे में देश के नेताओं को भारत विरोधी बयानबाजियां करने के बजाए हालात सुधारने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को अपने हालात का ध्यान रखना चाहिए।

मौलाना फजलुर रहमान का बयान तब आया है, जब शहबाज सरकार और असीम मुनीर पाकिस्तान के प्रांतों का बंटवारा करने की तैयारी में हैं। उन्होंने प्रांतों के बंटवारे का कड़ा विरोध किया और कहा कि जब देश पहले से ही आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव का सामना कर रहा है, ऐसे समय में प्रांतों के बंटवारा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''आज, जब देश आग और भुखमरी की चपेट में है, ऐसे नाजुक समय में प्रांतों के बंटवारे पर चर्चा की जा रही है।'' फजलुर रहमान ने कहा, ''हम भारत के साथ युद्ध और टकराव की बात करते हैं, लेकिन आइए हकीकत पर गौर करें।'' उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और उसके पास अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका और कानून-व्यवस्था जैसे अहम वैश्विक पैमानों पर अपनी स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।

'एक रात का क्या लोगी' फैंस ने की गंदी डिमांड !

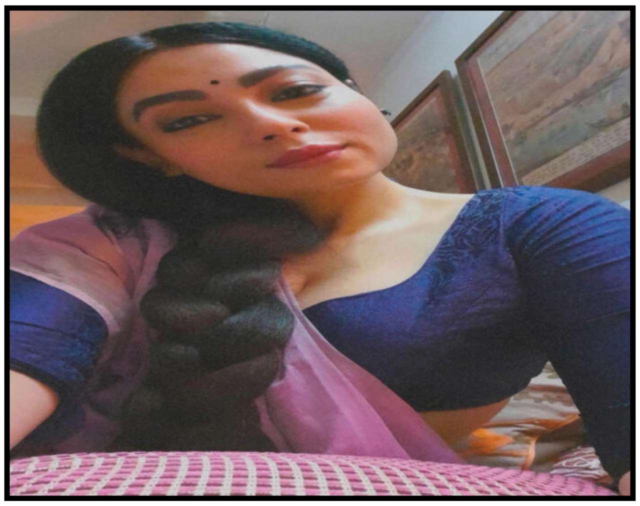

मुंबई : 'मिर्जापुर' में जरीना का बोल्ड किरदार निभाकर सुर्खियां बटोरने वाली अनंग्शा बिस्वास इन दिनों फिर चर्चा में हैं। एक इंटरव्यू में अनंग्शा ने बताया था कि किरदार की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी एक अलग ही इमेज बना ली थी। इसके बाद उन्हें बेहद आपत्तिजनक संदेश और अनुचित मांगों का सामना करना पड़ा। अनंग्शा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, 'मुझसे गंदी डिमांड की गई। मुझे मैसेज आ रहे थे कि एक रात का आप क्या लेंगी। आप २ दिन के लिए मॉरीशस आइए।' अभिनेत्री के मुताबिक, ऐसे संदेशों से उनके डीएम भर गए थे और यह अनुभव उनके लिए काफी परेशान करने वाला था। अनंग्शा ने कास्टिंग काउच का अनुभव भी साझा किया था। उनके मुताबिक, एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नामी निर्देशक की गर्लफ्रेंड बनने जैसी सलाह दी थी। हालांकि, उन्होंने साफ कर दिया।

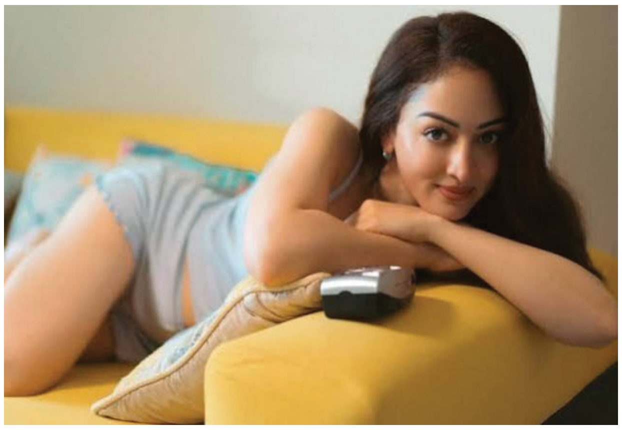

कश्मीर स्थित अपने पुश्तैनी घर लौटीं अभिनेत्री संदीपा धर

मुंबई : कुछ यादें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम ढूंढने नहीं जाते, बल्कि वे सही समय आने पर खुद हमारे सामने आ जाती हैं। अभिनेत्री संदीपा धर के लिए कश्मीर की हालिया यात्रा कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरी रही, जहां उन्हें अपने परिवार के इतिहास, भूली-बिसरी यादों और वादी की अनमोल खूबसूरती से फिर से जुड़ने का मौका मिला।

सोशल मीडिया पर अपनी इस यात्रा की झलकियां साझा करते हुए संदीपा ने लिखा है, "कुछ यादें ऐसी होती हैं, जिन्हें आप खोजने नहीं जाते, वे बस आपका इंतज़ार करती रहती हैं।" हाल ही में संदीपा अपने कश्मीर स्थित पुश्तैनी घर पहुंचीं, जो पलायन के बाद से लगभग उसी अवस्था में खड़ा है, न बिजली, न पानी और ना ही घर के भीतर अब बहुत कुछ बचा है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी बीते दशकों की कहानियों की गवाह हैं। इस दौरान उन्हें एक बेहद खूबसूरती से नक्काशीदार लकड़ी की अलमारी मिली, जो लगभग 80 से 90 साल पुरानी बताई जा रही है और आज भी लगभग सुरक्षित है।

इस खोज को याद करते हुए उन्होंने लिखा, "ऐसा लगा जैसे हमारे अतीत का एक छोटा-सा हिस्सा अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा है।" यह पल उनके लिए उन यादों और कहानियों का प्रतीक बन गया जो समय के साथ भी कहीं खोई नहीं है। फिलहाल, अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान उन्हें कुछ और अनमोल निशानियां भी मिलीं, जिसमें एक पुराने कपबोर्ड में उन्हें 30 से 40 साल पुराने एयर इंडिया के बोर्डिंग पास और बैगेज टैग भी मिले। संदीपा ने इन्हें "कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े, जो उस समय शायद महत्वहीन थे, लेकिन किसी तरह हर मुश्किल के बावजूद सुरक्षित रह गए" बताया है।

५०० मर्दों के सामने उतारे थे कपड़े !

मुंबई : दीया मिर्जा ने फिल्म 'तुमसा नहीं देखा' से जुड़ा एक पुराना किस्सा याद करते हुए ऐसा खुलासा किया, जिसने एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें बोल्ड सीन करना था। सेट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके चलते शुरुआत में यह अनुभव उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। दीया ने बताया, 'मुझे वैभवी मर्चेंट द्वारा हमारे साथ फिल्माया गया वह गाना याद है। यह ऐसा गाना था, जिसमें मुझे कपड़े उतारने थे और आखिर में ब्रा और अंडरवियर में रहना था। ऐसे में मेरे लिए सहज महसूस करना जरूरी था।' अभिनेत्री ने आगे बताया कि उनके सामने करीब ५०० लोगों की भीड़ थी, जिनमें सभी पुरुष थे, जबकि करीब २०० लोगों का दल भी मौजूद था, जिसमें ज्यादातर पुरुष थे। दीया के मुताबिक, इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि पुरुषों की घूरती निगाहों से प्रभावित हुए बिना भी वह अपनी नारी शक्ति और खूबसूरती का आनंद ले सकती हैं।

पुरुषों के अहंकार पर कसा तंज

मुंबई : दीपिका पादुकोण और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिल्म से दीपिका के बाहर होने को लेकर अब वांगा के भाई प्रणय वांगा के दावे ने नई हलचल पैदा कर दी है। दावा किया गया कि दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में १० फीसदी हिस्सेदारी मांगी थी, जिसे मंजूर नहीं किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लंबा पोस्ट शेयर कर सवाल उठाया कि जब पुरुष कलाकार लंबे समय से मुनाफे में हिस्सेदारी मांगते रहे हैं, तो महिला कलाकार के ऐसा करने पर इतना हंगामा क्यों? पोस्ट में इसे दोहरे मापदंड और 'मेल ईगो' से भी जोड़ा गया। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दीपिका ने इसी पोस्ट को लाइक कर दिया। उनके इस छोटे से रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है। बिना कुछ कहे दीपिका ने आखिर क्या संदेश दिया, इस पर अब खूब चर्चा हो रही है।

मुंबई: यूपी में नहीं दे पाए नौकरी इसलिए मुंबई आए...

मराठी भाषा के मुद्दे पर मंत्री प्रताप सरनाईक का अखिलेश यादव पर पलटवार

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने पर राजनीति गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट पर अब महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि मैं अखिलेश यादव से बस इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा कल्चर और सम्मान का ध्यान रखता है। पिछले कई सालों से नॉर्थ इंडियन लोगों को नौकरी के मौके नहीं मिले, जिसकी वजह से महाराष्ट्र पिछले 40-50 सालों से नॉर्थ इंडियंस को रोजी-रोटी दे रहा है। महायुति सरकार ऐसी सरकार है जो नौकरी देती है, छीनती नहीं। महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के निर्देश और ऑटो ड्राइवरों के विरोध पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके मामले को उठाया था। प्रताप सरनाईक ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है।

अखिलेश यादव ने उठाया था मुद्दा

अखिलेश यादव ने लिखा था कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है। मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं। क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है? अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियां मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा जोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही चलता है।

अखिलेश ने बीजेपी पर बोला था हमला

अखिलेश यादव ने लिखा था कि अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली-कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ओड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुडुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी। आखिर में उन्होंने लिखा था कि सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। आप अपने समय में नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए ये लोग महाराष्ट्र आए और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसे यूपी में चुनावी एजेंडा न बनाएं। राज्य में, हमने 1600-1800 टीचर (मराठी पढ़ाने के लिए) रखे हैं।

एफडीए का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन परिसरों पर एक्शन, 5 आउटलेट्स के फूड लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन परिसर में मौजूद 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा के नियमों के कथित उल्लंघन और साफ-सफाई, रख-रखाव व रेफ्रिजरेशन में भारी कमियां पाए जाने के बाद की गई है। बता दें कि एफडीए की तरफ से चलाए जा रहे एक राज्यव्यापी अभियान के तहत कुल 11 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिनमें अकेले 5 आउटलेट्स एमसीए परिसर के शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस अभियान के दौरान एफडीए ने राज्य भर में 45 होटलों, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान 25 जगहों पर छापे मारे गए और 33 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। ध्यान रहे कि एफडीए अधिकारियों ने 20 अगस्त को एमसीए को परिसरों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद आउटलेट्स पर कार्रवाई की गई। इसमें परमिट रूम, पवेलियन, मेडिटेरेनियन, ओरिएंटल स्विंग और क्वबे एंड पेस्ट्री काउंटर शामिल है। गौरतलब है कि इन सभी आउटलेट्स पर फूड हैंडलिंग (खाना संभालने के तरीके), स्टोरेज (भंडारण), रेफ्रिजरेशन और स्वच्छता के मानकों में गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके चलते प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।

'अगर हम पढ़े-लिखे होते तो ऑफिस में बैठते', मराठी नियम पर मुंबई के ऑटो ड्राइवरों की 3 दिन की हड़ताल

मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्सा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले ने राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज कर दी है। इसी बीच मुंबई में राज्य सरकार के इस फैसले के विरोध में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों का एक वर्ग सड़क पर उतर आया है। इन चालकों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि चालकों का विरोध ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा जानने के अनिवार्य नियम को लेकर है।

क्या कहना है कि गौर-मराठी भाषी चालकों का?

सरकार के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरे गैर-मराठी भाषी चालकों का कहना है कि इस नियम से उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और भारी-भरकम जुमार्ने का खतरा बढ़ गया है। हड़ताल में शामिल कई चालकों की उम्र 55 से 60 साल के बीच है। उनका कहना है कि वे कभी स्कूल नहीं गए, इसलिए उनके लिए अचानक मराठी बोलना और सीखना बहुत मुश्किल है। मामले में मुंबई कंदिवली लिंक रोड पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे एक ऑटो चालक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हम 55-60 साल के हैं। हम कभी स्कूल नहीं गए। हम मराठी कैसे बोल सकते हैं? अगर हम पढ़े-लिखे होते, तो किसी दफ्तर में बैठकर काम कर रहे होते।

इतना ही नहीं विरोध कर रहे चालकों का दावा है कि वे जैसे-तैसे टूटी-फूट मराठी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सहूलियत या समय देने के बजाय अधिकारियों द्वारा दंडित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि वे 15000 से 20000 रुपये तक का जुमार्ना कैसे भर सकते हैं? चालकों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक यह तीन दिन की हड़ताल जारी रहेगी।

दरार का दावा या सिर्फ भ्रम? माझीवाड़ा मेट्रो ब्रिज का सच, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

ठाणे : ठाणे जिले में कासारवडवली मेट्रो रूट 4 व 4ए (ग्रीन लाइन) पर गायमुख से कैडबरी जंक्शन तक 10.5 किलोमीटर लंबे रूट पर नवंबर महीने से मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावनाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने सनसनी फैला दी। जिसमें दावा किया गया कि मेट्रो पुल के पैनल में दरारें हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने माजीवाड़ा जंक्शन पर मेट्रो पुल का जायजा लिया। इस दौरान एमएमआरडीए के इंजीनियरों ने स्पष्ट किया कि पुल अंदर से पूरी तरह मजबूत है और घुमाव (कर्व) के कारण पैनल अलग दिख रहे हैं।

माजीवाड़ा जंक्शन पर मेट्रो ब्रिज के पैनल में दरारें दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसको लेकर लोग ब्रिज के कंस्ट्रक्शन स्थिति और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे।जिसके बाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर के माजीवाड़ा जंक्शन मेट्रो पुल का निरीक्षण किया। उप मुख्यंत्री शिंदे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरों से ब्रिज पैनल के मौजूदा स्टेटस के बारे में जाना। संबंधित अधिकारियों ने ब्रिज के टेक्निकल पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जनता का डर दूर करने के लिए पैनल की मजबूती की दोबारा जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से कसा जाये, यदि जरूरी हो, तो संबंधित पैनल को हटाकर ठीक से लगाया जाए, उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि ठाणे शहर के माजीवाड़ा जंक्शन पर मेट्रो ब्रिज के पैनल में दरारें दिखने के बारे में कुछ रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिसे संज्ञान में लेते हुए मैं इस ब्रिज की उस साइट पर आ कर एमएमआरडीए के इंजीनियरों की मदद से वस्तुस्थिति से अवगत हुआ हूं। निरीक्षण के दौरान मेट्री रूट के घुमाव के साथ कुछ पैनल नीचे से देखने पर ढीले दिखते हैं, लेकिन इन पैनल्स को लगाने के दौरान, उन्हें बीम कास्टिंग और स्टिचिंग के जरिए एक-दूसरे से जोड़ा जाता है। क्योंकि ये पैनल कास्टिंग से बने है, इसलिए ये एक ही साइज के है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर 4 ए, फ्लोर-जीआरडी, 29 डी, शबन हाउस, वंजावाडी लेन, माहिम वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400016 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhani.com